Powers of Tariff Advisory Committee regarding premium rates and conditions of insurance

1100. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the organisation that deals with premium rates and conditions of insurance;

(b) the powers of Tariff Advisory Committee in this regard; and

(c) the future of the insurance business?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) and (b) Tariff Advisory Committee (TAC) established under Section 64 U of the Insurance Act, 1938 is the authority to control and regulate the rates, advantages, terms and conditions that may be offered by insurers in respect of general insurance business.

In terms of Section 64 UC of the Insurance Act, 1938 the TAC may from time to time and to the extent it deems expedient, control and regulate the rates, advantages, terms and conditions that may be offered by insurers in respect of any risk or of any class or category of risks, the rates, advantages, terms and conditions of which, in its opinion, it is proper to control and regulate, and any such rates, advantages, terms and conditions shall be binding on all insurers.

(c) Regarding future of the insurance business in India, the Common Minimum Programme (CMP) of the Government lays down that—

"There is room for Public Sector Companies and private sector companies to co-exist and compete in the financial sector. We have gained considerable experience in the working of the banking sector. The said experience will be applied to the restructuring of the insurance industry, but at the same time, public sector companies like LIC, GIC etc. will be strengthened."

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रशासनिक खर्च

1101. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर, 1996 को दैनिक "इकोनामिक टाइम्स" में "चिदम्बरम बैंक्स शुड स्लैश एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रशासनिक खर्च अन्य बैंकों की तुलना में अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(क) वर्ष, 1996 के अन्त को समाप्त अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के व्यय के आंकड़ों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

व्यय	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
प्रचालन व्यय (कुल व्यय की तुलना में स्थापना व्यय का प्रतिशत सहित)	15135 (28.00%)	1130 (23.42%)	1324 (24.80%)
कुल व्यय की तुलना में स्थापना व्यय का प्रतिशत	11136 (20.60%)	653 (13.53%)	466 (08.73%)
कुल आय की तुलना में स्थापना व्यय का प्रतिशत	11136 (20.75%)	653 (12.18%)	466 (07.65%)

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान

1102. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए लगभग 40,000 करोड़ रुपए मूल्य के अग्रिम ऋणों का समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या-क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त राशि का एक बड़ा भाग बड़े और मझौले औद्योगिक क्षेत्रों के पास पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो बड़े व मझोले औद्योगिक क्षेत्रों के पास कितनी-कितनी राशि पड़ी हुई है और लघु तथा कृषि क्षेत्रों में कितनी-कितनी राशि होने का अनुमान है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों की कुल राशि लगभग 40,000 करोड़ रुपए थी, जिसमें से लगभग 26,000 करोड़ रुपए राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित थे।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा डाटा बेस से 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार बड़े एवं मझौले उद्योग तथा कृषि आदि के रूप में वर्गीकृत राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों के ब्यौरों के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, दिनांक 31.3.96 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

	(करोड़ रुपए में)
सरकारी क्षेत्र की इकाइयां	595.37
गैर-प्राथमिकता क्षेत्र	13803.62
प्राथमिकता क्षेत्र	12065.05
जोड़	26464.04

External auditing to check mistakes in Financial Institution

1103. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA:

DR. MOHAN BABU:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce external auditing for financial institutions besides inspections by the RBI to detect mistakes;

(b) if so, when it is proposed to be introduced; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) and (b) The accounts of All-India Financial Institutions (AIFIs) such as Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation of India Limited, Industrial Reconstruction Bank of India and Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited are being audited every year by statutory/external auditors.

It may also be added that a Board for Financial Supervision (BFS) was constituted under the aegis of Reserve Bank of India (RBI) in November 1993 to oversee the supervision of financial system comprising banks, AIFIs and non-banking financial companies. At present, AIFIs are subjected to 'On-site' inspections bi-annually.

(c) Does not arise.

Defaulting industrial houses in repayment of loans

1104. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the year-wise defaults from industrial sector for repayment of loans and interest to All India Industrial Finance Institution/ Corporations during the last three years, year-wise;

(b) which industrial houses have been major defaulters and their year-wise and institution-wise defaults during the last three years;

(c) what measures have been taken to recover outstanding dues and with what results; and

(d) whether there is any policy for not granting loans to any of the units of the defaulting industrial houses, by the Financial Institutions; if so, the details thereof; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House to the extent available and permissible under the rules.

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार युवकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

1105. **श्री अजीत जोगी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या कितनी है, जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने संबंधी योजना के अंतर्गत अपने स्वयं के उद्योग लगाने हेतु